

'चुनाव में किये 50 से 55 प्रतिशत वादे एक साल में पूरे किये'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सदन में नये विधायकों को मौका मिलेगा व सीनियर विधायकों के अनुभव का उपयोग होगा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। | विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जयपुर, 30 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संकल्प पत्र के 50 से 55 प्रतिशत वादे पूरे कर चुकी है। हमने किसान, महिला, युवा एवं मजदूर सहित हर वर्ग के लिए काम किए हैं तथा इतने कम समय में सभी काम धरातल पर उतर भी रहे हैं। शर्मा ने गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

एक वर्ष का परफॉर्मंस अच्छा रहा है। ऐसे में, विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार को इन सभी उपलब्धियों को सदन में मजबूती के साथ रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान की प्राथमिकताओं को समझते हुए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जहां संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णय लिए गए हैं, वहीं, बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा किसानों को दिन में बिजली

देने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर निवेश लाया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि नए विधायकों को सदन में पूरा मौका मिले तथा सीनियर विधायकों के अनुभव का उपयोग करते हुए वे सदन की स्वस्थ परम्पराएं कायम रखें। मुख्यमंत्री ने विधायकों से विधानसभा में अपनी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और सदन में सरकार के निर्णयों को मजबूती से रखने की अपील की तथा विधानसभा के नियम-

- भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों को सरकार की उपलब्धियाँ सदन में मजबूती से रखने के लिये कहा।
- विधायक दल की बैठक में प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में हुई श्रद्धालुओं की मृत्यु पर दो मिनट का मौन रखा गया।

प्रक्रियाओं के समुचित अध्ययन सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार आमजन की सरकार है। विकास पुरुष मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तथा राज्य सरकार के लिए राज्य का विकास ही सबसे ऊपर है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित, मंत्रीगण एवं भाजपा के सभी विधायक उपस्थित रहे। बैठक में प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर दो मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया।

महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिये जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली, 30 जनवरी। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर 'चूक, लापरवाही और प्रशासन की पूर्ण विफलता' का आरोप लगाते हुए, उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को एक जनहित दायर की गई। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सभी राज्य सरकारों को महाकुंभ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है। महाकुंभ में गत 29 जनवरी की रात मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई और 60 अन्य के घायल हो गए थे।

अधिवक्ता तिवारी की याचिका में घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने और अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए कानूनी कार्रवाई

- अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की है।

शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

तिवारी ने अपनी याचिका में कहा कि भगदड़ सरकारी अधिकारियों की चूक, लापरवाही और प्रशासन की पूरी तरह विफलता के कारण लोगों को खराब स्थिति और भाग्य को दर्शाती है।

जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो ज्यादातर आम और गरीब लोग ही इसके शिकार बनते हैं। किसी भी कार्यक्रम या समारोह में जाने वाले अति विशिष्ट लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है।

यहां तक कि किसी अधिकारी, राजनेता या अति विशिष्ट व्यक्ति के गुजरने पर आम लोगों की आवाजाही भी रोक दी जाती है।

विमान -हैलिकॉप्टर टक्कर में 60 मरे

वांशिंगटन में बुधवार को अमरीकी एयरलाइन्स का विमान हवा में सेना के हैलिकॉप्टर से टकरा गया था

- अधिकारियों के अनुसार विमान में 60 यात्री व 4 चालक दल सदस्य थे। हादसे में किसी के भी जीवित बचे होने की उम्मीद नहीं है। अब तक 28 शव मिल चुके हैं। सेना के हैलिकॉप्टर में तीन लोग सवार थे।

होने के बाद किसी के भी जीवित बचने की उम्मीद पूरी तरह से धूमिल हो गयी है। उन्होंने कहा कि जब विमान रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट टकराया, उस समय विमान में 60 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे तथा सैन्य हेलीकॉप्टर में तीन लोग सवार थे।

आपातकालीन सेवा प्रमुख जॉन डोनेली ने बताया कि अब तक 28 शव बरामद किए जा चुके हैं। परिवहन सचिव सीन डफ्री ने कहा कि आसमान साफ था और पायलट भी अनुभवी थे, पर वहां 'जसर कुछ हुआ', जिससे दोनों वायुयान आपस में टकरा गये थे। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच

की जा रही है सैन्य हेलीकॉप्टर विमानों के निर्धारित रास्ते पर कैसे उड़ रहा था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी सवाल किया कि हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं उड़ रहा था या उसके पायलट ने विमान को आते देखकर अपना मार्ग क्यों नहीं बदला।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि पेंटागन स्थिति पर सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए तैयार है।

अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन ने बताया कि हवा में टक्कर कल रात करीब नौ बजे हुई। विमान, कंसास के विचिटा हवाई अड्डे से उड़ान परी थी।

'सर्दी से मरने वालों की रिपोर्ट एक सप्ताह में दें'

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। भारतीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में इस बार सर्दी के मौसम में 56 दिनों के भीतर 474 बेघर व्यक्तियों की कथित मौत की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए, दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस भेज कर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग की गुरुवार को जारी एक विज्ञापन में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि आयोग ने इस संबंध में मीडिया की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें बेघर लोगों के साथ काम करने वाले एक गैर

सरकारी संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) के हवाले से कहा गया है कि राजधानी में इस सर्दी के मौसम में 56 दिनों के भीतर लगभग 474 लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ये मौतें 15 दिसंबर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 के बीच हुई हैं, क्योंकि गर्म कपड़े, कंबल और पर्याप्त आश्रय जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की अनुपलब्धता है। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के कथित दावे के अनुसार, दिल्ली में लगभग 80 प्रतिशत अज्ञात शव बेघर व्यक्तियों के हैं।

'हिन्दुस्तान का ...'

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दुनिया को पीछे छोड़ने वाली आर्थिक ग्रोथ के बावजूद, भारत का रोजगार-बाजार अपनी विशाल युवा जनसंख्या को नियमित वेतन प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। पिछले बरत में, भारत ने रोजगार पैदा करने वाली विभिन्न योजनाओं पर पाँच साल में 24 अरब डॉलर खर्च करने के लिये रखे थे, लेकिन वे योजनाएं अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं, अभी उन पर विस्तृत चर्चाएं ही हो रही हैं।

चीन का नया एआई ऐप 'डीपसीक'...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किया था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) ने भारतीय बलों को हरया और भारतीय क्षेत्र में अंदर तक घुस गए। यह संघर्ष पश्चिमी क्षेत्र में अक्सर चिन और पूर्व क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश (तत्कालीन नेपा) को लेकर विवादों से उत्पन्न हुआ था। चीन ने दोनों क्षेत्रों को अपनी भूमि का हिस्सा बताया, जबकि भारत ने इन्हें ऐतिहासिक समझौतों के आधार पर अपनी संपत्ति बताया।

हालिया मानचित्र और डिजिटल टूलस, जो चीन के प्रभाव में तैयार किए गए हैं, तबाना और भारत के अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के हिस्सों पर चीन के दावे को मजबूत करते रहते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं, जैसे 1962 के भारत-चीन युद्ध, के चारों ओर विकसित हो रहे एआई निर्देशित नैरेटिव, चीन द्वारा घरेलू और वैश्विक, दोनों क्षेत्रों में सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का एक रणनीतिक प्रयास है।

डीपसीक एआई की इतिहास की पुनः व्याख्या एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें देश, जनरेटिव एआई मॉडलों का उपयोग करके राजनीतिक नैरेटिव्स को मजबूत करते हैं। चीन द्वारा

1962 के युद्ध को "आवश्यक रक्षात्मक कार्रवाई" के रूप में प्रस्तुत करना वर्तमान भूराजनीतिक रणनीति में फिट बैठता है, जिसका उद्देश्य भारतीय सीमा पर अपनी आक्रामक मुद्रा को न्यायोचित ठहराना है। भारत को उसका निवादा बताते हुए, डीपसीक चीन की भूमिका के अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को फिर से आकार देने की कोशिश करता है। एआई द्वारा नैरेटिव की गई सामग्री में दलाई लामा के 1959 में भारत भागने और उसके बाद भारत में शरण लेने को एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना करार दिया है, जिसके कारण चीन को अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन द्वारा अचानक किए गए सैन्य आक्रमणों और क्रूर युद्धों को कम करके दिखाया गया है, जिनकी वजह से भारत को भारी सामरिक झटके लगे थे। जहाँ तक वास्तविक दुनिया में इसके प्रभावों का सवाल है, एआई-निर्मित आख्यान (नैरेटिव) संवदेनशील सीमा वार्ताओं के दौरान तनाव बढ़ा सकते हैं। डिजिटल युग में ऐसी सामग्री जनमत और नीति निर्माण को प्रभावित कर सकती है और इससे भी ज्यादा, इतिहास को पुनः लिखने के प्रयास देशों को क्षेत्रों पर अपने दावे करने के लिए हिम्मत देते हैं तथा भावी

घुसपैठ को उचित ठहराते हैं। भारत ने अब इस संभावना को "सार्वजनिक बहस" का आकार देने में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, विशेषकर महत्वपूर्ण भूराजनीतिक मुद्दों पर घरेलू एआई क्षमताओं, काउंटर-नैरेटिव रणनीतियों और डिजिटल साक्षरता अभियानों को मजबूत करना देशों द्वारा प्रायोजित मिथ्या जानकारी के प्रभाव को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है।

डीपसीक के एआई एप्लिकेशनों की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने तकनीकी उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसके कारण एनविडीया जैसी कंपनियों को मार्केट वैल्यू काफ़ी गिर गई है। हालाँकि, डीपसीक के एआई एप्लिकेशनों को तेजी से अपनाए जाने के कारण डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह ऐप यूजर डेटा को चीन में संग्रहीत करता है, जिससे चीनी सरकार द्वारा यूजर के डेटा के शोषण का खतरा हो सकता है। इसके अलावा, डीपसीक द्वारा चीनी सेंसरशिप कानूनों को पालन करने से मिथ्या जानकारी तथा दुष्प्रचार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

महाकुंभ नगर नो व्हीकल ज़ोन घोषित, प्रयागराज में सिर्फ दुपहिया वाहनों को अनुमति

बुधवार के हादसे के बाद राज्य सरकार ने कई सख्त कदम उठाए

- प्रयागराज की 8 सीमाओं को सील कर दिया है ताकि भीड़ नियंत्रण में मदद मिल सके। राज्य सरकार ने सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए तथा कहा कि वीआईपी मूवमेंट की सूचना एक सप्ताह पहले उपलब्ध करानी होगी।
- अभी बसंत पंचमी, महाविश्वरात्रि और माघी पूर्णिमा का महास्नान होना है और इन अवसरों पर भी भारी भीड़ जुटने का अनुमान है।
- बुधवार के हादसे के बाद गुरुवार को भी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। गुरुवार को शाम तक 1.77 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया।

महाकुम्भनगर, 30 जनवरी। महाकुंभ में मंगलवार 29 जनवरी को देर रात हुई भगदड़ में मौतों के बाद मेला क्षेत्र में सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब पूरे मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल ज़ोन घोषित कर दिया गया है। अब किसी भी तरह के वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरे प्रयागराज शहर में चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। सिर्फ बाइक चल सकती है।

मेला क्षेत्र में आने-जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने और सभी वीआईपी पास रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। चार फरवरी तक श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम तक जाने की इजाजत होगी। प्रयागराज शहर में भी 4 पहिया गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। शहर में सिर्फ बाइक, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को जाने की अनुमति होगी।

मौनी अमावस्या के हादसे से सबक लेते हुए सरकार ने मेला क्षेत्र के भीतर रास्ते को वन-वे कर दिया है। अब श्रद्धालुओं को वन-वे के बाद दूसरे रास्ते से वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा, प्रयागराज में आने वाले 8 प्रमुख बॉर्डरों को बंद कर दिया गया है, जिससे भीड़ नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार द्वारा जारी संकुलर में स्पष्ट किया गया है कि वीआईपी व

वीवीआपी मूवमेंट को लेकर एक सप्ताह पहले ही सूचना उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाविश्वरात्रि के स्नानों पर श्रद्धालुओं से प्रस्तावित भारी भीड़ के बीच धैर्य बनाए रखने की विनती करते हुए इन तिथियों व इसके आसपास ऐतिहासिक बरतने की अपील भी की गई है। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आना जारी

रहा। मंगलवार देर रात हुई भगदड़ की घटना का यहां आ रहे श्रद्धालुओं पर कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश सरकार के अनुसार, गुरुवार को शाम चार बजे तक 1.77 करोड़ लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई।

उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) मेला, वैभव कृष्ण ने गुरुवार को कहा कि पुलिस आगामी बसंत पंचमी (तीन फरवरी) पर अमृत

स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त में लगी है। पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को भीड़ का दबाव अपेक्षाकृत कम हुआ है और सभी पुल फिरो से खोल दिए गए हैं जिससे मेला क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सके। हालांकि, बसंत पंचमी के पूर्व बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए प्रमुख स्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

डीआईजी ने स्पष्ट किया कि मौनी अमावस्या की तरह आगामी अमृत स्नान पर भी विशेष व्यक्तियों (वीआईपी) की आवाजाही पर रोक बनी रहेगी। पुलिस अधीक्षक (यातायात) अंशुमान मिश्रा ने बताया कि मेला में भीड़ कम होने तक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जब तक भीड़ मेला क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाती, बाहर की गाड़ियों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

कांग्रेस की भांति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पार्टी में बुलाया गया और पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया। यहिदुरप्पा ने इसका परिणाम भी दिया। लेकिन संगठनात्मक फेर बदल में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहिदुरप्पा को शिफ्ट कर दिया और उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यहिदुरप्पा के आलोचक खुलकर सामने नहीं आ पाए। उन्हें डर था कि पार्टी में उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा और उन्हें राजनीति से बाहर किया जा सकता है। पर अब पार्टी नेता सामने आ रहे हैं और विजयेन्द्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठा रहे हैं। बसनगौडा पाटिल यतनाल के

नेतृत्व में एक गुट सक्रिय हो गया है। उन्हें अन्य नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कई विधायकों और पूर्व मंत्रियों को अपनी तरफ कर लिया है, जिनमें यहिदुरप्पा गुट के कई नेता भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विद्रोह कर रहे नेताओं की फिफ्ट यही है कि अगले चुनाव तक कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और इसमें तीन साल का वक्त है।

लेकिन पार्टी का एक गुट है, जो मानता है कि केन्द्रीय नेतृत्व दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक के मसले पर ध्यान दे सकता है।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दोनों वहाँ बनी झोपड़ी में चार दिन तक पति-पत्नी की तरह रहे। इस दौरान, प्रकाश ने उसकी मर्जी से रोजाना संबंध बनाए। पीड़िता ने अदालत को यह भी बताया कि प्रकाश से उसके रिस्ते की बात भी चल रही थी। वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता को उग्र साबित नहीं है। अभियुक्त की ओर से कहा गया कि भट्टा संचालक ने भी अपने बयान में पीड़िता को बालिग होने के आधार पर ही काम पर रखने का बयान दिया है, जिससे साबित है कि पीड़िता बालिग थी और दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। ऐसे में उसे पाँक्सो और दुष्कर्म के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने पीड़िता को नाबालिग मानते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है।

'मैरिट के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) छह पदों को भरना था। याचिकाकर्ता के मैरिट में आने पर उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। इसके लिए जारी मैरिट लिस्ट में याचिकाकर्ता को एम्बवीसी वर्ग में छठे स्थान पर बताया गया। याचिका में कहा गया कि दस्तावेज सत्यापन के बाद विभाग ने अंतिम मैरिट सूची जारी की, लेकिन उसमें एम्बवीसी वर्ग से केवल पांच अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया। वहीं, छठे स्थान पर आई याचिकाकर्ता को चयन से वंचित कर दिया। ऐसे में उसे नियुक्ति दी जाए।



प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण परिवारों का सर्वे प्रारम्भ

सबके लिए आवास

कार्यालय ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद में सम्पर्क कर पंजीकृत सर्वेयर द्वारा सर्वेक्षण अथवा

पात्र परिवार द्वारा आवास प्लस 2024 व Aadhaar FaceRD एप पर स्वयं सर्वे की सुविधा उपलब्ध

स्वयं के मोबाइल से भी सर्वे अपलोड करने का प्रावधान

- लाभार्थी मोबाइल फोन में QR Code से एप डाउनलोड करें।
- आधार कार्ड, नरेगा जाँब कार्ड एवं बैंक पासबुक, भूमि संबंधी जानकारी मोबाइल एप पर अपलोड करें।
- सर्वे पूर्ण होने पर सर्वे अपलोड (submit) करना होगा, अन्यथा सर्वे पूर्ण नहीं होगा।
- स्वयं सर्वे अपलोड करने की जानकारी विभाग की वेबसाइट <https://rdprd.rajasthan.gov.in> से प्राप्त करें।

www.rural.nic.in

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार

www.rdprd.rajasthan.gov.in



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री



आवास प्लस 2024 एप
डाउनलोड हेतु



Aadhaar FaceRD एप
डाउनलोड हेतु